तमिलनाडु आवास समिति

बनाम

ए. विस्वम (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से

9 फरवरी, 1996

[के. रामास्वामी और जी.बी. पटनायक, न्यायमूर्तिगण]

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894:

धाराएं- 11, 12, 16, 18, 30-पंचाट-विशेष भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति-उन सभी द्वारा अपने दावों को प्रस्तुत किया जाना-भूमि अर्जन अधिकारी ने उचित रूप से न्यायालय में क्षतिपूर्ति जमा की-सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात मकानों के निर्माण और सार्वजनिक पार्क के लिए अर्जित भूमि-भूमि का केवल एक हिस्सा छोड़ा नहीं जा सकता-इसलिए अधिसूचना में उल्लिखित सभी भूमियों के संबंध में अर्जन पूर्ण है-इसलिए प्रश्नगत भूमि सहित भूमियों का कब्जा लिया गया होना चाहिए-इसलिए वास्तविक स्वामी, अर्थात आवास समिति के विरुद्ध व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता।

बलवंत नारायण भागडे बनाम एम.डी. भागवत और अन्य, **[1975] सप्ली. एस.सी.आर. 250, संदर्भित।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1996 की दीवानी अपील संख्या 3617-18

मद्रास उच्च न्यायालय के आर.पी. संख्या 81/94 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 16.3.95 से तथा एस.ए. संख्या 1526 वर्ष 1988 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 7.4.94 से।

अपीलकर्ताओं के लिए हरीश साल्वे, ए. मरिअरपुथम, श्रीमती अरुणा माथुर और अजय कुमार।

उत्तरदाताओं संख्या 3-8 और 11 के लिए आर.एफ. नरीमन, एस. नंद कुमार, एल.के. पांडे।

उत्तरदाताओं संख्या 9 के लिए एस. शिवसुब्रमण्यम और एम.ए. चिन्नासामी।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया :

विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।

विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 7 अप्रैल, 1994 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न हुई हैं, जो 1988 की एस.ए. संख्या 1526 में पारित किया गया था। तथ्य विवाद में नहीं हैं।

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1) (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 17 सितंबर, 1958 को मद्रास शहर की नियोजित विकास के लिए "भाग । नेबरहुड स्कीम" के रूप में ज्ञात और पुनर्रोधित "अशोक नगर स्कीम" के रूप में नामांकित कोदम्बाक्कम और पुदूर गांवों से मिलकर बनी 339 एकड़ भूमि के एक बड़े हिस्से का अर्जन करते हुए प्रकाशित की गई थी। धारा 6 के अंतर्गत घोषणा 26 नवंबर, 1958 को प्रकाशित की गई थी। भूमि अर्जन अधिकारी ने धारा 11 के अंतर्गत अपना पंचाट 28 फरवरी, 1966 को दिया। अपीलकर्त्ता का यह मामला है कि भूमि अर्जन अधिकारी ने 28 फरवरी, 1966 को भूमि का कब्जा ले लिया था और 21 मार्च, 1966 को अपीलकर्त्ता को कब्जा सौंप दिया था। यह विवाद में नहीं है कि इस योजना के अधीन 3639 से अधिक आवासीय मकानों का निर्माण करके उनका कब्जा सौंप दिया गया है। योजना में एक एकड़ और बत्तीस सेंट के विस्तार की विवादित भूमि सार्वजनिक पार्क के लिए अलग रखी गई है जो नगर पालिका में निहित हो गई थी।

उत्तरदाता का यह मामला है कि वह वाद दायर करने की तिथि, अर्थात 19 अप्रैल, 1984 से पहले के 30 से अधिक वर्षों से भूमि का स्वामी है और उसका उस पर हक और कब्जा है तथा अपीलकर्त्ता ने उसके कब्जे और उपभोग को बाधित करने का प्रयास किया था। परिणामस्वरूप, उसने अपीलकर्त्ता के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश के लिए वाद दायर किया। स्वीकृत

रूप से, वह अप्पाराव मुदलियार का एक सेवक था। विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया। अपील पर, नगर दीवानी न्यायाधीश ने वाद डिक्री कर दिया और उच्च न्यायालय ने उसकी पुष्टि कर दी। इस प्रकार विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें हैं।

उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एफ. नरीमन द्वारा यह तर्क दिया गया है कि व्यादेश के एक सामान्य वाद में, यद्यपि आनुषंगिक रूप से हक पर आधारित है, न्यायालयों से यह निष्कर्ष लेखबद्ध करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या उत्तरदाता वाद की तिथि को भूमि के कब्जे में थे और यदि कब्जे में होने का निष्कर्ष लेखबद्ध किया जाता है तो वे वास्तविक स्वामी के अतिरिक्त हर किसी के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश के हकदार हैं। इस मामले में, तीनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से तथ्य के रूप में पाया कि उत्तरदाता वाद की तिथि को भूमि के कब्जे में थे। अपीलकर्त्ता ने यह सिद्ध नहीं किया था कि भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा उत्तरदाताओं से कब्जा लिया गया था। इसके द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा धारित अधिकार, हक और रुचि अधिनियम की धारा 16 के संचालन से अलग नहीं हुई थी। इसलिए, उत्तरदाता वैध स्वामी बने रहे। तदनुसार, वे अपीलकर्त्ता-समिति सहित हर किसी के विरुद्ध व्यादेश के हकदार हैं। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने *बलवंत नारायण भागडे बनाम एम.डी. भागवत और अन्य,* [1975] सप्ली. एस.सी.आर. 250 पर गहरा भरोसा किया।

प्रश्न यह है: क्या वह आधार जिस पर विद्वान अधिवक्ता ने मामले को अनुमानित किया है, विधिक रूप से स्वीकार्य विधिक आधार पर आधारित है? यह सत्य है कि जब उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के रूप में विचार किया है और तथ्य के रूप में कब्जे पर एक निष्कर्ष लेखबद्ध किया है, तो सामान्यतः यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए, ऐसे निष्कर्ष को स्वीकार करेगा और सार्वजनिक महत्व के कानून के सारवान प्रश्न का निर्णय करने के लिए उस आधार पर आगे बढ़ेगा। जैसा कि पहले कहा गया है, क्या उच्च न्यायालय ने उस आधार पर कदम बढ़ाया है, यही प्रश्न है। पूरे सम्मान के

साथ, विद्वान न्यायाधीश ने अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के संचालन पर ध्यान दिए बिना एक तथ्य लेखबद्ध करने की कार्यवाही की है, स्वीकृत या सिद्ध तथ्यों से विधिक निष्कर्ष निकालने में विफल रहे हैं और गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकाला है कि अर्जन समाप्त हो गया है जो कि प्रत्यक्ष त्रुटि का गठन करता है जिससे कानून का सारवान प्रश्न उत्पन्न होता है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि भूमि का अर्जन अधिनियम के अधीन धारा 6 के अंतर्गत घोषणा के उचित प्रकाशन के बाद किया गया था। जैसा कि कुछ उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. शिवसुब्रमण्यम ने उचित रूप से तर्क दिया है, सार्वजनिक प्रयोजन की निश्चयात्मकता स्थापित हो जाती है। उसके बाद, अधिनियम के अध्याय III में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना आवश्यक है और तथ्य के रूप में, स्वीकृत रूप से, भूमि अर्जन अधिकारी ने 28 फरवरी, 1966 को अपना पंचाट दिया और धारा 12 के अंतर्गत सूचना पत्र जारी किया। प्रश्नगत भूमि के संबंध में छोड़कर सभी पक्षकारों ने क्षतिपूर्ति प्राप्त की। कानून के एक मामले के रूप में धारा 30 के अंतर्गत, जब दावेदार/स्वामी विरोध के साथ या उसके बिना क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है, तो भूमि अर्जन अधिकारी को उसका भुगतान करना चाहिए। यदि किसी ने क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की, तो वह धारा 30 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति को उस न्यायालय में जमा करने के लिए बाध्य है जिसमें धारा 18 के अंतर्गत निर्देश दिया जा सकता है और तदनुसार धारा 30 के अंतर्गत निर्देश देने के लिए बाध्य है। साक्ष्य से यह देखा गया है कि भूमि अर्जन अधिकारी ने पाया कि एक अप्पावू मुदलियार और नटराज मुदलियार की सर्वेक्षण संख्या 140/4 की एक एकड़ और बत्तीस सेंट के विस्तार की भूमि में रुचि थी। तदनुसार, अपने पंचाट में उन्होंने उल्लेख किया कि चूंकि उन सभी ने दावा प्रस्तुत किया था, इसलिए उन्होंने धारा 30 के अंतर्गत विवाद को संदर्भित किया और न्यायालय में क्षतिपूर्ति जमा की। इसके परिणामस्वरूप, कब्जा ले लिया जाएगा और उसके बाद भूमि धारा 16 के अंतर्गत सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाती है।

प्रश्न यह है: क्या प्रश्नगत भूमि का कब्जा लिया गया था? यह मुद्दा सीधे प्रत्यर्थियों के संबंध में उठता है। दुर्भाग्यवश, उत्तरदाताओं ने उस भूमि अर्जन अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया था जिसने कब्जा लिया था और अपीलकर्त्ता को भूमि का कब्जा सौंपा था। यह विवाद में नहीं है कि प्रदर्श पी-5 के अंतर्गत, भूमि अर्जन अधिकारी ने अपीलकर्त्ता को कब्जा सौंपा था। इसलिए, जैसा कि अपीलकर्त्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे ने उचित रूप से तर्क दिया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ई) के अंतर्गत उपधारणा परिणामस्वरूप इस मामले के तथ्यों पर आकर्षित होगी। भूमि अर्जन अधिकारी ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में अन्य भूमियों के साथ विवादित भूमि का कब्जा लेने के बाद, बदले में उसे अपीलकर्त्ता को सौंप दिया था। यह देखा गया है कि एक सामान्य अधिसूचना द्वारा अर्जित 339 एकड़ भूमि ली गई थी और पंचाट दिया गया था तथा सभी भूमियों का कब्जा लिया गया था। प्रश्न उठता है: क्या भूमि अर्जन अधिकारी के लिए संपूर्ण 339 एकड़ भूमि का वास्तविक कब्जा लेना और उसे आवास समिति को सौंपना संभव होगा? प्रश्न के प्रति दृष्टिकोण व्यावहारिक और यथार्थवादी होना चाहिए परंतु विशुद्ध रूप से विधिक नहीं होना चाहिए। यह सत्य है कि *बलवंत नारायण भागडे* के मामले में, अंटवालिया, न्यायमूर्ति ने पृष्ठ 263 पर इस प्रकार अवधारित किया था:

> "प्रश्न यह है कि कब्जा लेने का तरीका क्या है? अधिनियम इस बिंदु पर मौन है। जब तक कि संबंधित पक्षकार के लिखित समझौते द्वारा कब्जा न लिया जाए, कब्जा लेने का तरीका स्पष्ट रूप से प्राधिकारी के लिए भूमि पर जाने और कोई ऐसा कार्य करने का होगा जो यह संकेत दे कि प्राधिकारी ने भूमि का कब्जा ले लिया है। यह ढोल पीटकर या अन्यथा घोषणा के रूप में हो सकता है या मौके पर एक लिखित घोषणा लटकाकर हो सकता है कि प्राधिकारी ने भूमि का कब्जा ले लिया है"

भगवती, न्यायमूर्ति (जैसा कि वे तब थे) ने दो सदस्यों के लिए बोलते हुए यह अवधारित किया था कि:

"नागरिक प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायिक निर्णयों द्वारा समझे गए अर्थ में 'प्रतीकात्मक' कब्जा लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। न ही केवल कागज पर कब्जा होना पर्याप्त होगा। अधिनियम भूमि को सरकार में निहित करने की एक आवश्यक शर्त के रूप में भूमि का वास्तविक कब्जा लेने की परिकल्पना करता है। ऐसा कब्जा किस प्रकार लिया जाना आवश्यक होगा जैसा कि भूमि की प्रकृति स्वीकार करती है। ऐसा कोई पक्का नियम नहीं बनाया जा सकता जो यह तय करे कि ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए कौन-सा काम काफ़ी होगा। इसलिए, हमें यह एक पूर्ण और अनुलंघनीय नियम निर्धारित करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि केवल मौके पर जाना और ढोल पीटकर या अन्यथा घोषणा करना प्रत्येक मामले में भूमि का कब्जा लेने के गठन के लिए पर्याप्त होगा। परंतु यहाँ, हमारे मत में, चूंकि भूमि परती पड़ी थी और सामग्री के समय उस पर कोई फसल नहीं थी, इसलिए तहसीलदार का मौके पर जाना और यह निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए भूमि का निरीक्षण करना कि कौन सा हिस्सा बंजर और कृषि योग्य है और इसलिए उसका कब्जा लिया जाना चाहिए और उसके विस्तार का निर्धारण करना, कब्जा लेने के गठन के लिए पर्याप्त था। यह प्रतीत होता है कि जब तहसीलदार द्वारा यह किया गया था तब अपीलकर्ता उपस्थित नहीं था, परंतु कब्जा प्रभावी करने के लिए भूमि के स्वामी या अधिभोगी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। विधिक आवश्यकता के मामले के रूप में यह भी कड़ाई से आवश्यक नहीं है कि भूमि के स्वामी या अधिभोगी को सूचना पत्र दिया जाना चाहिए कि कब्जा एक विशेष समय पर लिया जाएगा, यद्यपि जहां संभव हो वहां प्राधिकारियों द्वारा कब्जा लेने से पहले ऐसा सूचना पत्र देना वांछनीय हो सकता है क्योंकि इससे

अधिभोगी या स्वामी को कभी भी पता चले बिना केवल कागजी कब्जा लेने के किसी भी धोखाधड़ी या मिलीभगत के संव्यवहार की संभावना समाप्त हो जाएगी।"

इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा यह सुस्थापित कानून है कि अर्जित भूमि का कब्जा लेने के स्वीकृत तरीकों में से एक भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा उसके/उनके द्वारा हस्ताक्षरित साक्षियों की उपस्थिति में एक ज्ञापन या पंचनामा लेखबद्ध करना है और वह भूमि का कब्जा लेने का गठन करेगा क्योंकि अर्जित भूमि का वास्तविक कब्जा लेना असंभव होगा। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि कुछ मामलों में स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति भूमि का कब्जा लेने में सहयोग नहीं कर सकता है।

यह देखा गया है कि स्वयं उत्तरदाता द्वारा लिखे गए एक पत्र में, उक्त सर्वेक्षण संख्या की भूमि पर समिति के हक को स्वीकार करते हुए, उसने वैकल्पिक स्थल के आवंटन की मांग की थी। दूसरे शब्दों में, जब तक कब्जा नहीं लिया जाता और वह हक से वंचित नहीं हो जाता और वही अपीलकर्त्ता में निहित नहीं हो जाता, तब तक वह अपीलकर्त्ता से उसे वैकल्पिक स्थल प्रदान करने का अनुरोध नहीं कर सकता है। यह उसका मामला नहीं है कि उस चरण पर वह अभी भी विवादित भूमि पर हक रखना जारी रख रहा था। स्वीकृति उसके हित के असंगत है। वह इससे भी अवगत था कि पंचाट दिया गया था और कब्जा स्पष्ट रूप से उसके अधीन लिया गया होना चाहिए था। यह सत्य है कि सामान्यतः कब्जा हक का नौ गुना होता है। यदि उस सिद्धांत को अवैध रूप से अनधिकृत अधिवास द्वारा सार्वजनिक अर्जन तक विस्तारित किया जाता है, तो पूर्ववर्ती स्वामी के पास अपनी पूर्ववर्ती भूमि पर अतिक्रमण करके क्षतिपूर्ति के साथ-साथ भूमि का कब्जा भी होता है और वह दावा करता है कि वह कब्जे में बना रहा। ऐसा निर्माण सार्वजनिक प्रयोजन को विफल कर देगा। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, भूमि अर्जन अधिकारी अन्य भूमियों के साथ सर्वेक्षण संख्या 140/4 की भूमि का कब्जा लेने और अपीलकर्त्ता को सौंपने के तथ्य के बारे में बोलने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है परंतु उसे वाद में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में अभियोजित नहीं किया गया

था। यह देखा गया है कि जब उत्तरदाता अर्जित भूमि पर अपने विधिक हक का दावा कर रहा है, तो उसे आवश्यक रूप से सरकार को पक्षकार के रूप में अभियोजित करना चाहिए था और सरकार के विरुद्ध अपने कब्जे का दावा करना चाहिए था। वह नहीं किया गया था। समिति ने भूमि अर्जन अधिकारी से कब्जा प्राप्त कर लिया है, उससे यह सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि भूमि अर्जन अधिकारी ने भूमि का कब्जा कैसे लिया था।

इस मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट होगा कि सर्वेक्षण संख्या 140/4 में 1.33 एकड़ सहित 339 एकड़ से मिलकर बनी भूमि का कब्जा लिया गया होना चाहिए। यह देखा गया है कि जब शहर के नियोजित विकास के लिए भूमि अर्जित की गई थी और इमारतों का एक बड़ा हिस्सा पहले ही निर्मित किया जा चुका है और लगभग 1 एकड़ 32 सेंट मापने वाली भूमि पार्क के प्रयोजन के लिए अलग रखी गई है, तो स्पष्ट रूप से अन्य भूमियों के साथ विवादित भूमि का कब्जा लिया गया था और योजनाओं के अनुसार निर्माण किया गया था। क्या अपीलकर्त्ता के लिए, आवास समिति को कब्जा सौंपे बिना, ऐसे बड़े निर्माण करना और सर्वेक्षण संख्या 140/4 वाली भूमि के केवल इस हिस्से को छोड़ देना संभव होगा जो सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात पार्क की सार्वजनिक सुविधा के लिए अलग रखा गया था? योजना का निर्माण भूमि का कब्जा लेने और उसका सीमांकन करने तथा निर्माण कार्य किए जाने के बाद ही सामने आएगा। यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि कब्जा अभी भी प्रत्यर्थियों के पास था और भूमि अर्जन अधिकारी ने भूमि के केवल इस टुकड़े का कब्जा नहीं लिया था। यह उत्तरदाता का मामला नहीं है कि उसने भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा लेने का विरोध किया था और उसके बाद भूमि अर्जन अधिकारी ने उसे बेदखल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। एकल न्यायाधीश ने इन सुसंगत तथ्यों और स्थापित तथ्यों से उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने इस आधार पर विचार करने की कार्यवाही की कि चूंकि अर्जित भूमि का उपयोग भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए नहीं किया गया था और कब्जा नहीं लिया गया था, इसलिए अर्जन समाप्त हो गया था। जिला

न्यायाधीश द्वारा दिया गया तर्क भी उतना ही त्रुटिपूर्ण है। उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में पूरी तरह से अवैध है। जिला न्यायाधीश ने इस आधार पर कदम बढ़ाया कि राजस्व अभिलेखों में अपीलकर्त्ता का नाम नामांतरित नहीं दिखाया गया है और भूमि अपीलकर्त्ता के नाम पर पंजीकृत नहीं थी। ये परिस्थितियाँ पूरी तरह से अवैध और अनुचित हैं। अधिनियम की धारा 51 के साथ पठित धारा 11(4) स्वयं अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के पंजीकरण से छूट देती है। जिला न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से वैधानिक उपबंधों की अनदेखी की थी। आवास समिति के लिए राजस्व अभिलेखों में भूमियों का नामांतरण कराना और उसमें अपना नाम दर्ज कराना अनावश्यक था। यह इसके प्रयोजन के लिए नहीं था। यह सार्वजनिक प्रयोजन के लिए था, अर्थात मकानों के निर्माण और उसके जरूरतमंद व्यक्तियों को आवंटन के लिए। मकानों के निर्माण के बाद, सार्वजनिक पार्क अर्जन में निहित हो गया। स्पष्ट रूप से, इस चरण पर नगरपालिका अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए कब्जा लेने के लिए आती जब भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया था। इस चरण पर, उत्तरदाताओं को सूचना पत्र दिया गया था और उत्तरदाता ने शाश्वत व्यादेश के लिए वाद दायर किया।

इस प्रकार विचार करने पर, सर्वेक्षण संख्या 140/4 की भूमि का हक अपीलकर्त्ता में निहित होने के कारण, वह पूर्व में जिसके किसी की भी रही हो, वह उससे/उनसे विभाजित हो गई और कोई भी उक्त अर्जित भूमि पर एक बार फिर से कोई दावा नहीं कर सकता और उस आधार पर व्यादेश की मांग नहीं कर सकता। इसलिए, व्यादेश वास्तविक स्वामी, अर्थात आवास समिति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, जिसमें भूमि अंततः निहित हो गई थी और फिर नगर निगम को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक अतिचारी स्वामी के विरुद्ध व्यादेश का दावा नहीं कर सकता और न ही न्यायालय इसे जारी कर सकता है।

इस प्रकार विचार करने पर, हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय के डिक्री की पुष्टि करने में कानून की गंभीर त्रुटि की गई थी। तदनुसार, प्रथम

अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय की डिक्री और निर्णय अपास्त किए जाते हैं और विचारण न्यायाधीश का निर्णय बहाल किया जाता है।

तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। कोई लागत नहीं।

जी.एन. अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।